

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना : राजस्थान प्रथम स्थान पर
2.	राजस्थान का राज्य वृक्ष - खेजड़ी
3.	देश का पहला शत - प्रतिशत 9 बीमित गाँवों वाला ज़िला - अलवर
4.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सेलरेटर (AISA) 2. भारत बोध - आपणी माटी आपणो खेल 3. राजस्थान 55 वर्ष बाद संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप के क्वार्टर फाइनल में 4. MGUMST और भारतीय सेना के मध्य MoU 5. ICDS निदेशालय का ग्रीन अरावली अभियान के तहत पौधरोपण का लक्ष्य 6. राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोगों के मध्य MoU 7. पिपलांत्री गांव (राजसमंद) 8. 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी हेंडबॉल प्रतियोगिता (19 वर्ष)
5.	भील जनजाति व तांत्या मामा
6.	काजीरंगा का क्रमिक विकास
7.	राज्य वित्त: 2025-26 के बजट का अध्ययन' रिपोर्ट
8.	चक्र (CHAKRA) उत्कृष्टता केंद्र
9.	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
10.	भारत-अमेरिका व्यापार समझौता, 2026
11.	कुष्ठ रोग
12.	ठोस ईंधन डक्टेड रैमजेट तकनीक



राजस्थान परिदृश्य



प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना : राजस्थान प्रथम स्थान पर



चर्चा में क्यों?

- 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' के तहत जारी रैंकिंग में राजस्थान राज्य ने जनवरी, 2026 माह में देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं
महिला एवं बाल विकास विभाग

मातृशक्ति को समर्पित
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
में महिलाओं और शिशुओं के पोषण एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र
में जनवरी 2026 की रैंकिंग के अनुसार राजस्थान को
देशभर में
प्रथम स्थान



मुख्य बिन्दु:

- लाभार्थियों के पंजीकरण, लाभार्थियों को भुगतान एवं 30 दिवस में लाभार्थियों को नकद लाभ अंतरण, कुल प्राप्त परिवारों के त्वरित निस्तारण के पैरा मीटर्स पर योजना में समग्र प्रगति के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है।

--2--

'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' (PMMVY)

- **शुरुआत :** केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2017 को केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना के रूप में।
- यह योजना महिला सशक्तीकरण से संबंधित भारत सरकार के 'मिशन शक्ति' का एक प्रमुख घटक है।
- **मंत्रालय :** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
- **प्रावधान :** योजना अंतर्गत प्रथम बार गर्भवती हुई महिला को दो किस्तों में ₹5000 तथा द्वितीय बार गर्भवती हुई महिला को केवल बालिका के जन्म एवं टीकाकरण पूर्ण करने पर ₹6000 की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।

उद्देश्य :

- दिहाड़ी में होने वाली हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति हेतु नकद प्रोत्साहन प्रदान करना ताकि महिला पहले बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त आराम कर सकें;
- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार लाना।
- यदि दूसरी संतान बालिका है, तो उसके लिए अतिरिक्त नकद प्रोत्साहन प्रदान करके बालिकाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना।

राजस्थान का राज्य वृक्ष - खेजड़ी

चर्चा में क्यों?

- 2 फरवरी, 2026 को बीकानेर में हजारों पर्यावरण प्रेमियों द्वारा राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी सहित राज्य में हो रही पेड़ों की कटाई के विरोध में आंदोलन की शुरुआत की गई। साथ ही, 363 संतों और स्थानीय लोगों ने खेजड़ली बलिदान की याद में अनिश्चितकालीन अनशन भी शुरू किया।

मुख्य बिन्दु:

- आंदोलनकारियों की मुख्य माँग प्रदेश में 'वृक्ष संरक्षण कानून' (Tree Protection Act) को तुरंत लागू करने तथा 50 वर्ष से पुराने सभी पेड़ों की सुरक्षा के लिए नियम बनाने से संबंधित है।
- ज्ञातव्य है कि राजस्थान में बढ़ती सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण के परिणामस्वरूप खेजड़ी के पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है।

फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

खेजड़ी:

- वानस्पतिक नाम - प्रोसोपिस सिनेरेरिया।
- उपनाम - जांटी, शमी वृक्ष (ग्रन्थों में), सीमलो, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्पवृक्ष/थार का कल्पवृक्ष।
- सर्वाधिक खेजड़ी - नागौर जिले में।
- सर्वाधिक खेजड़ी वाला क्षेत्र - शेखावाटी।
- खेजड़ी के फूल - नीमझर/मींझर, हराफल - सांगरी, पत्तियाँ - लूम/लूंग।
- खेजड़ी पर वर्ष 1988 में 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया।

Daily Current Affairs

Date : 04 February, 2026



- **राज्य वृक्ष घोषित** : 31 अक्टूबर, 1983
- खेजड़ली गाँव (जोधपुर) में वर्ष 1730 में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी को बचाने के लिये पेड़ों से चिपककर अपना बलिदान दिया था। यह घटना तत्कालीन मारवाड़ शासक अभयसिंह के शासन काल की है।
- प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन खेजड़ली में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है।
- 12 सितम्बर, 1978 में पहली बार खेजड़ली दिवस मनाया गया था। तब से प्रति वर्ष 12 सितम्बर को खेजड़ली दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- मांगलियावास (अजमेर) में कल्प वृक्ष (खेजड़ी के पुराने दो वृक्ष) है जहाँ हरियाली अमावस्या को मेला लगता है।
- **माटो** - बीकानेर के राजचिह्न में खेजड़ी वृक्ष दर्शाया गया है, इसे माटो कहा जाता है।
- **थार शोभा** - केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान (CIAH), बीकानेर द्वारा विकसित खेजड़ी की कांटे रहित किस्म।

--5--

देश का पहला शत - प्रतिशत 9 बीमित गाँवों वाला ज़िला - अलवर



चर्चा में क्यों?

- अलवर देश का पहला ज़िला बन गया है, जहाँ के 9 गाँवों के निवासियों का शत - प्रतिशत बीमा सम्पन्न हो चुका है।



मुख्य बिन्दु:

- इन 9 गाँवों में अलवर का देसूला, लक्ष्मणगढ़ का अंतापाड़ा, कठूमर का हनुमंता, रामगढ़ का लालपुर, गोविंदगढ़ का पालनखेड़ा, मालाखेड़ा का बिचपुरी, बिलोटा का मारोड़ खुर्द, थानागाजी का कोडलका तथा झारखेड़ा का भुल्ला का बाँस शामिल हैं।
- भारत सरकार और भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा 'वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा' (Insurance for All by 2047) का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक प्रत्येक नागरिक और उद्यम के पास उचित बीमा सुरक्षा हो।
- **देसूला ग्राम पंचायत** : अगस्त, 2025 में अलवर की देसूला ग्राम पंचायत देश की पहली ऐसी ग्राम पंचायत बनी थी, जहाँ सभी निवासियों को बीमा कवर प्रदान किया गया था।
- **फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:**
- **मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना** : राज्य में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAAY) (पूर्व में चिरंजीवी योजना) राज्य के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं और बीमा कवर प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है।
- **शुरुआत** : 1 मई, 2021 से।
- **प्रावधान** : यह योजना प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹25 लाख तक का कैशलेस उपचार/ईलाज प्रदान करती है, जिसमें ₹5 लाख रुपये बीमा मोड में और ₹20 लाख रुपये ट्रस्ट मोड में होते हैं। साथ ही अंग प्रत्यारोपण और कोक्लियर इम्प्लांट्स के लिए विशेष पैकेज भी शामिल हैं।
- इस योजना को केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के साथ एकीकृत करके संचालित किया जा रहा है।

Daily Current Affairs

Date : 04 February, 2026



वार्षिक प्रीमियम :

- इस योजना के नये चरण में प्रति परिवार ₹1,965 का प्रीमियम निर्धारित किया गया है, जो योजना में 1,819 पैकेजों को कवर करता है, जिनमें से 1,761 पैकेज बीमा मोड में और 58 पैकेज ट्रस्ट मोड में हैं।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC), छोटे और सीमांत किसानों, संविदा श्रमिकों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवारों, वरिष्ठ नागरिक (70 वर्ष से अधिक आयु) और कोविड-19 से प्रभावित व्यक्तियों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम। शेष परिवार ₹850 प्रति परिवार वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके इस योजना में शामिल हो सकते हैं, शेष प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।
- **MAA कोष** : योजना के सफल क्रियान्वयन और वित्तीय पूर्ति के लिए राजस्थान बजट - 2025-26 में ₹3500 करोड़ का 'MAA कोष' निर्मित किया गया है।

--7--

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सेलरेटर (AISA)</p> <ul style="list-style-type: none">■ जयपुर के झालाना स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज कैंपस में राज्य का पहला और एकमात्र अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सेलरेटर (AISA) की स्थापना की जाएगी।■ अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सेलरेटर (AISA) राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे युवाओं में नवाचार, उद्यमिता और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।■ संबंधित विभाग : सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग।■ AISA के माध्यम से राज्य में रोबोटिक्स, कोडिंग, एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स का हब विकसित हो सकेगा।
2.	<p>भारत बोध - आपणी माटी आपणो खेल</p> <ul style="list-style-type: none">■ आयोजन : राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।■ उद्घाटन : स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष नीरज के. पवन।■ भारत बोध - आपणी माटी आपणो खेल एक सांस्कृतिक खेल पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय जड़ों, पारंपरिक खेलों और क्षेत्रीय विरासत को बढ़ावा देना है।
3.	<p>राजस्थान 55 वर्ष बाद संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप के क्वार्टर फाइनल में</p> <ul style="list-style-type: none">■ राजस्थान की फुटबॉल टीम ने 79वीं संतोष ट्रॉफी (वर्ष 2025-26) में इतिहास रचते हुए 55 वर्ष बाद (अंतिम बार 1971) नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।■ हालांकि क्वार्टर फाइनल मुकाबले में राजस्थान को रेलवे ने 0-2 से हराया।

4.

MGUMST और भारतीय सेना के मध्य MoU

- हाल ही में, भारतीय सेना और महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी (MGUMST), जयपुर के मध्य एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
- **उद्देश्य** : इस समझौते का मुख्य लक्ष्य सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों और उनके बच्चों के लिए चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है।
- **NEET के माध्यम से प्रवेश** : जो सैन्य परिवारों के बच्चे NEET के जरिए मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में प्रवेश लेंगे, उन्हें प्रतिवर्ष ₹1 लाख की छात्रवृत्ति दी जाएगी।
- **पैरामेडिकल छात्र** : एलाइड हेल्थ और पैरामेडिकल कोर्सेज के छात्रों को उनकी वार्षिक ट्यूशन फीस का एक-तिहाई हिस्सा छात्रवृत्ति के रूप में मिलेगा।

5.

ICDS निदेशालय का ग्रीन अरावली अभियान के तहत पौधरोपण का लक्ष्य

- महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान द्वारा ICDS (एकीकृत बाल विकास सेवाएँ) निदेशालय के माध्यम से आगामी 1 वर्ष में 2 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह पौधरोपण ग्रीन अरावली अभियान के तहत किया जाएगा।
- ये पौधे राज्य के 63,000+ आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगाए जाएंगे।
- **नोट** : राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 2025-26 में 'ग्रीन अरावली डवलपमेंट प्रोजेक्ट' के लिए ₹250 करोड़ की स्वीकृति दी गई।
- **अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट** : मार्च, 2023 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर 'अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट' को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य चार राज्यों में अरावली हिल रेंज के आसपास 5 किमी. के बफर क्षेत्र में हरियाली का विस्तार करना है।

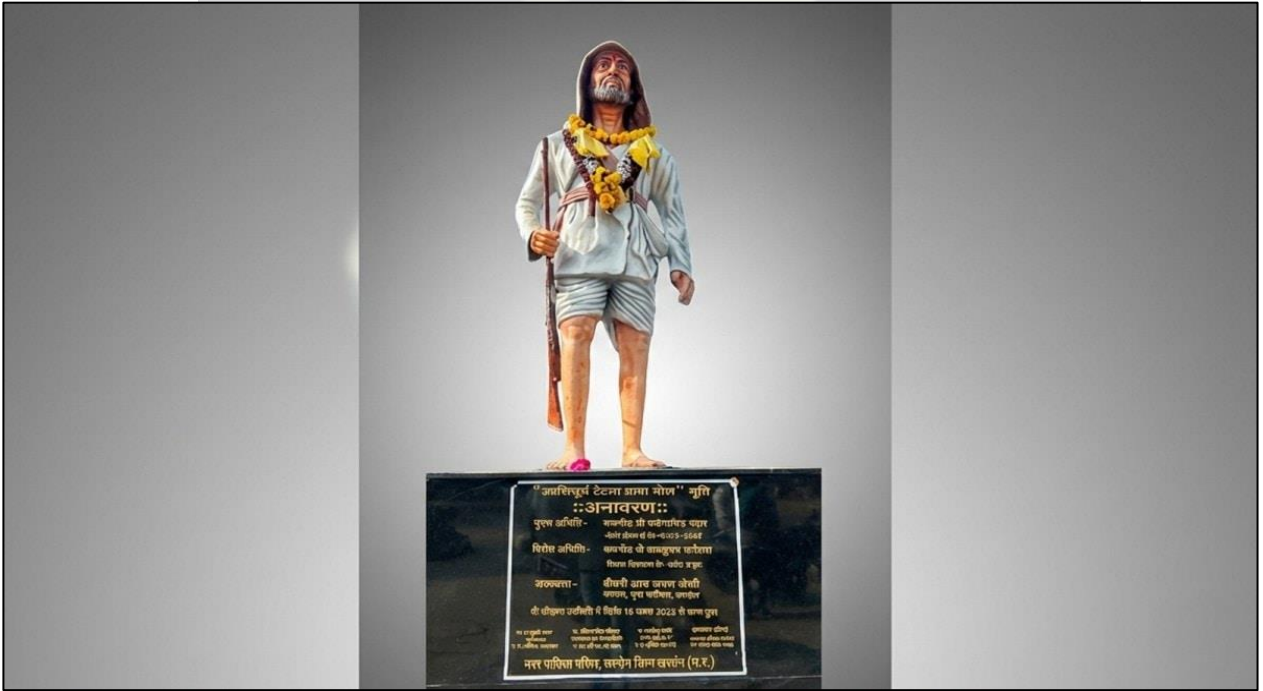
6.	<p>राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोगों के मध्य MoU</p> <ul style="list-style-type: none">■ राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बीच हाल ही में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) संपन्न हुआ।■ उद्देश्य : राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के सुचारु, निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करना।■ इस MoU के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग को स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कुल 30 हजार कंट्रोल यूनिट एवं 60 हजार बैलेट यूनिट किराये पर उपलब्ध कराई जाएगी।■ राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त : राजेश्वर सिंह।
7.	<p>पिपलांत्री गांव (राजसमंद)</p> <ul style="list-style-type: none">■ हाल ही में, उदयपुर पर्यटन विभाग ने पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध राजसमंद के पिपलांत्री गाँव को एक प्रमुख 'वर्ल्ड क्लास रूरल टूरिज्म डेस्टिनेशन' के रूप में विकसित करने के लिए चुना।■ पिपलांत्री देश का एक ऐसा मॉडल ग्राम है, जहाँ हर बेटे के जन्म पर 111 पौधे लगाने की अनूठी परम्परा है।■ इस परंपरा की शुरुआत वर्ष 2005 में गाँव के पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल द्वारा की गई, जिन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है।
8.	<p>69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी हैंडबॉल प्रतियोगिता (19 वर्ष)</p> <ul style="list-style-type: none">■ आयोजन : 27 से 31 जनवरी, 2026 तक सोमनाथ (गुजरात) में।■ राजस्थान का प्रदर्शन : राजस्थान की U-19 बालक वर्ग टीम ने रजत पदक जीता। राजस्थान की टीम को गुजरात ने हराया।

इतिहास एवं संस्कृति

भील जनजाति व तांत्या मामा

चर्चा में क्यों?

- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भील समुदाय के तांत्या मामा की धातु प्रतिमा स्थापित कि जाएगी।



मुख्य बिन्दु:

तांत्या मामा:

- परिचय:** भील समुदाय के प्रमुख आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी।
- योगदान:** 1857 की क्रांति के पश्चात् राजस्व उत्पीड़न और आदिवासी समुदायों के शोषण होने के कारण वर्ष 1878 से 1889 के मध्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का सक्रिय प्रतिरोध किया।
- यह धनी जमींदारों और ब्रिटिश समर्थकों से धन लुटकर गरीबों व आदिवासी समुदाय में पुनर्वितरण के कारण तांत्या मामा को भारतीय रॉबिन हुड की संज्ञा दी गई।

भील जनजाति:

- 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। (अनुसूचित जनजाति आबादी का 37.7%)।
- **निवासी** : मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आन्ध्रप्रदेश।
- औपनिवेशिक शासन के विरोध के कारण वर्ष 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम में 'आपराधिक जनजाति' घोषित किया गया।

प्रमुख विद्रोह:

- **भगत आंदोलन (वर्ष 1908)**: गोविंद गिरी के नेतृत्व में सम्प सभा (वर्ष 1883) की स्थापना की गई तथा 14 नवंबर, 1913 को मानगढ़ पहाड़ी (बाँसवाड़ा, राजस्थान) पर आदिवासी जलियाँवाला मानगढ़ हत्याकाण्ड हुआ।
- **एकी आंदोलन (वर्ष 1920)**: मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में।
- **सांस्कृतिक विरासत** : पिथोरा चित्रकला (मध्यप्रदेश) और भील कला (बिंदुदार शैली) जैसी विशिष्ट कला शैलियों और भगोरिया (मध्यप्रदेश) और गोल गढ़ेड़ो (गुजरात) जैसे त्योहारों।

भूगोल एवं भू-विज्ञान

काजीरंगा का क्रमिक विकास

चर्चा में क्यों?

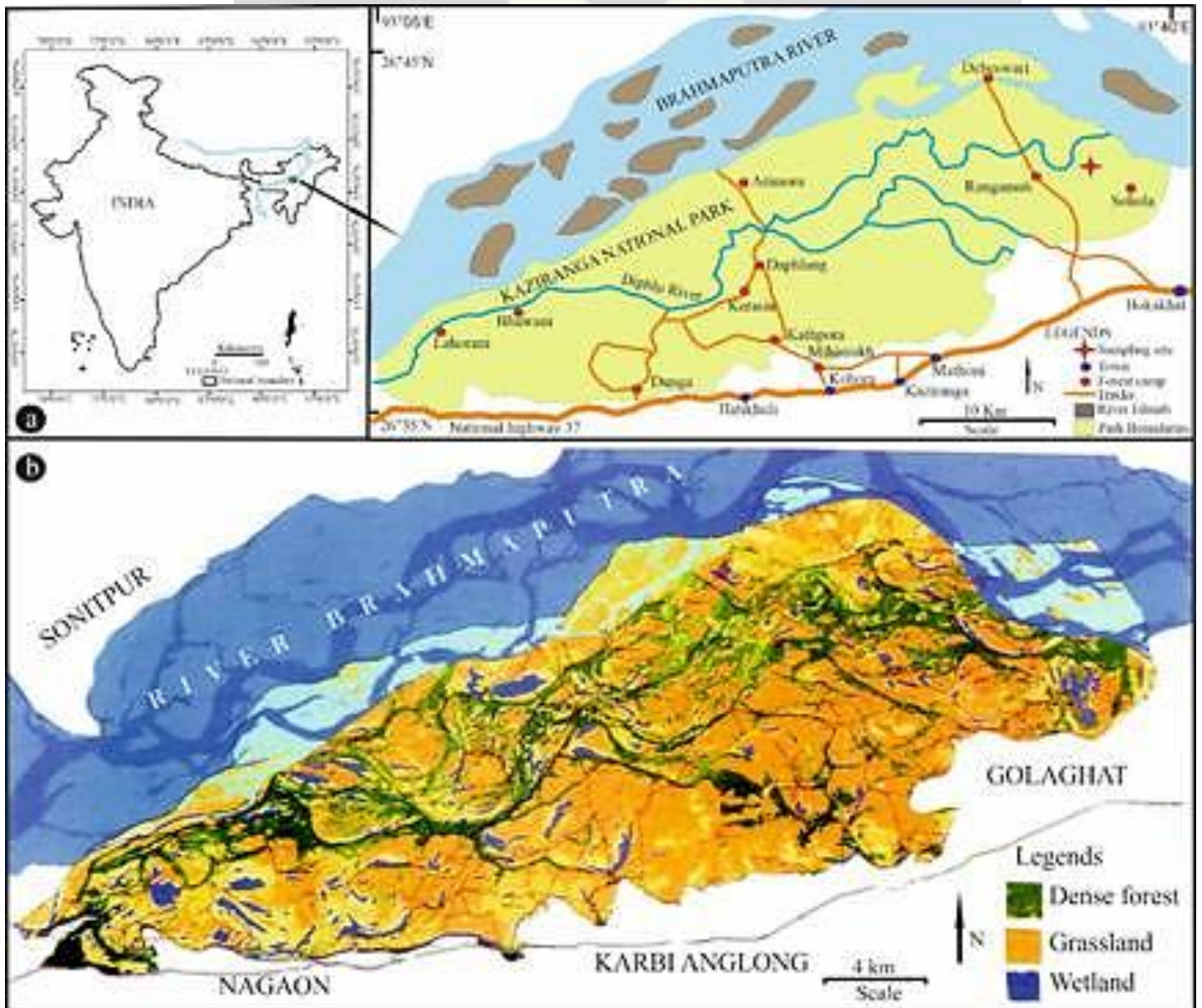
- बीरबल साहनी पैलियोसाइंसेस संस्थान (BSIP), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) का एक स्वायत्त संस्थान, के वैज्ञानिकों ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (KNP) की आर्द्रभूमि के नीचे की मिट्टी से परागकणों का उपयोग करके केएनपी में पैलियोशाकाहारी गतिविधियों से संबंधित पहले दीर्घकालिक पैलियोइकोलॉजिकल रिकॉर्ड का पता लगाया।



मुख्य बिन्दु:

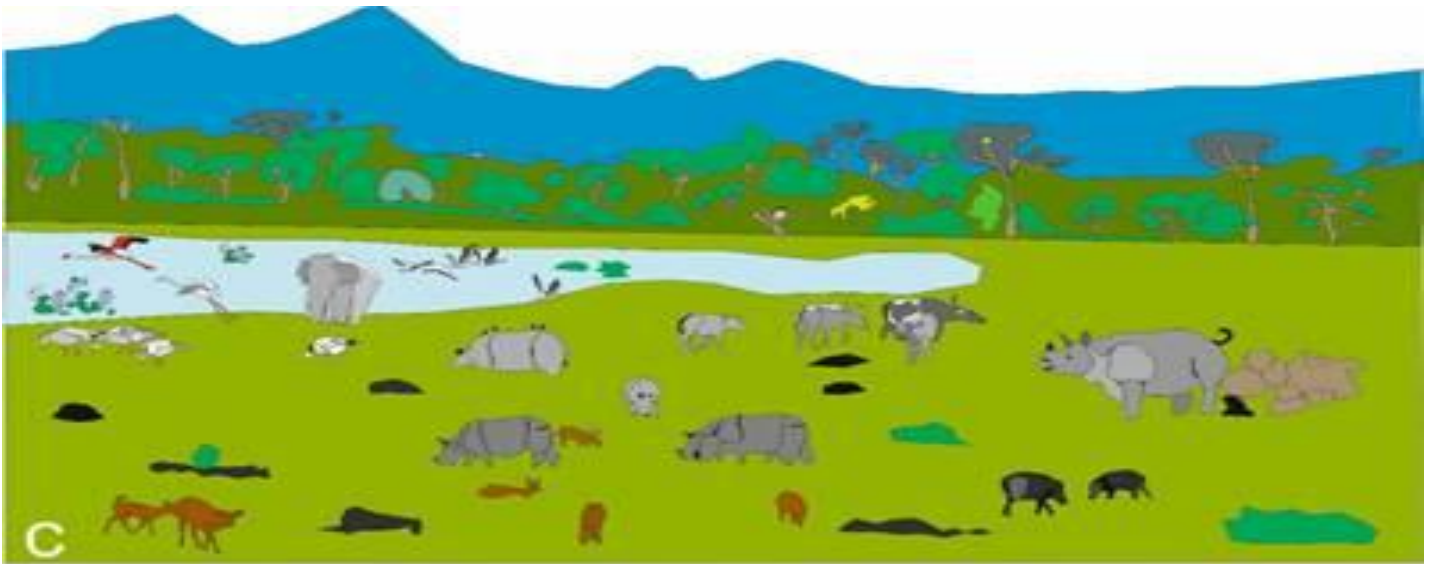
अध्ययन:

- शोधकर्ताओं ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के सोहोला दलदली क्षेत्र से एक मीटर से थोड़ा अधिक लंबा तलछटी कोर निकाला। परत दर परत, यह मिट्टी एक प्राकृतिक अभिलेखागार की तरह काम करती है, जो अतीत के सूक्ष्म निशानों को संरक्षित रखती है।
- इन निशानों में उन पौधों के परागकण और साथ ही, उन कवक के बीजाणु शामिल हैं, जो पशु मल पर पनपते हैं।



Daily Current Affairs

Date : 04 February, 2026



-:15:-

जर्नल 'कैटेना' (एल्सेवियर) में प्रकाशित अध्ययन का निष्कर्ष:

- **काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का क्रमिक विकास:** जीवाश्म साक्ष्यों के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि काजीरंगा का वर्तमान परिदृश्य इसके अतीत से स्पष्ट रूप से भिन्न है और यह दर्ज करता है कि उत्तर-पश्चिमी भारत में लेट होलोसिन के दौरान, विशेष रूप से लिटिल आइस एज और बढ़ती मानव गतिविधियों के कारण, भारतीय गैंडे सहित बड़े-बड़े शाकाहारी जानवरों की क्षेत्रीय विलुप्ति हुई।
- **एक सींग वाले भारतीय गैंडे के अंतिम प्रमुख आवास:** यह प्रजाति कभी भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक रूप से फैली हुई थी, लेकिन होलोसिन काल से इसका वितरण काफी कम हो गया। पिछले लगभग 3300 वर्षों में, पूर्वोत्तर भारत तुलनात्मक रूप से जलवायु की दृष्टि से स्थिर रहा और यहां मानव दबाव कम रहा, जबकि उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में आवास हास, जलवायु की गिरावट और अति-शिकार के कारण गैंडों को पूर्व की ओर पलायन करना पड़ा और अंततः वे काजीरंगा में केंद्रित हो गए।

अन्य विवरण:

- बाढ़, सूखा, भूकंप और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ, तेज़ी से हो रहा शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और वनों की कटाई वैश्विक पारिस्थितिकी हास को बढ़ावा दे रहे हैं और जैव विविधता के नुकसान की गति तेज कर रहे हैं।
- पूर्वोत्तर भारत, जो इंडो-बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है, उन कई संकटग्रस्त प्रजातियों का आवास है, जिनके विलुप्त होने का खतरा है।
- लेट क्वाटर्नरी मेगाफॉना विलुप्तियाँ वैश्विक रूप से बड़ी चिंता का विषय बनी हुई हैं, जिनके कारण अब भी विवादित हैं; आज, विश्वभर में लगभग 60% बड़े शाकाहारी जानवर संकट में हैं, और दक्षिण-पूर्व एशिया में सबसे अधिक जोखिमग्रस्त प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, बड़े शाकाहारी जानवरों - विशेष रूप से एक-सींग वाला भारतीय गैंडा - का प्रमुख केंद्र है।

आर्थिक घटनाक्रम

राज्य वित्त: 2025-26 के बजट का अध्ययन' रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 'राज्य वित्त : 2025-26 के बजट का अध्ययन' रिपोर्ट जारी की है।



मुख्य बिन्दु:

RBI की राज्य वित्त रिपोर्ट वर्ष 2025-26:

- राज्यों में जनसांख्यिकीय विविधता :
 - युवा राज्यों को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार सृजन पर अधिक खर्च करने की आवश्यकता है।
 - मध्यम आयु वर्ग के राज्यों को बुनियादी ढाँचे, शहरी सुधारों और महिला कार्यबल की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

Daily Current Affairs

Date : 04 February, 2026



- वृद्ध राज्यों को स्वास्थ्य सेवा, पेंशन और सामाजिक कल्याण की बढ़ती लागतों के लिए तैयार रहना चाहिए।
- 2. **राजकोषीय घाटे में वृद्धि** : राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 3.3% हो गया।
 - **कारण**: केंद्र से प्राप्त अनुदानों में कमी।
- 3. **राजस्व वृद्धि हेतु राज्यस्तरीय सुधार** : राज्यों का अपना कर आधार अत्यधिक केंद्रित है। जिसमें राज्य GST, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और स्टाम्प, कुल कर संग्रह का 90% हिस्सा रखते हैं।
- 4. **राजस्व व्यय**:
 - **पूँजी निवेश** : केंद्र सरकार की राज्यों को पूँजी निवेश हेतु विशेष सहायता योजना में समर्थन से पूँजीगत व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है (2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.2%)।
 - **सामाजिक व्यय**: वित्त वर्ष 2025-26 में राजस्व व्यय प्रमुख चालक सामाजिक क्षेत्र व्यय है (GDP का 8.2%)।
- 5. **ऋण और उधार** : राज्यों का समेकित ऋण मार्च, 2021 में 31% के उच्चतम स्तर से घटकर मार्च, 2024 में GDP का 28.1% हो गया, लेकिन मार्च, 2026 तक इसके बढ़कर 29.2% होने का बजटीय अनुमान है।
- 6. **अनुसंधान व्यय**: राज्यों का अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय कम है (GDP का 0.2 से 0.3%)।
 - चिकित्सा व कृषि अनुसंधान पर किया गया व्यय अधिक है।

--:18:--

चक्र (CHAKRA) उत्कृष्टता केंद्र

चर्चा में क्यों?

- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने 8 उभरते क्षेत्रों (सनराइज़ सेक्टर्स) के वित्तपोषण समर्थन हेतु एक समर्पित उत्कृष्टता केंद्र 'चक्र' (CHAKRA) की शुरुआत की।



मुख्य बिन्दु:

- **परिचय:** SBI द्वारा बनाया गया एक ज्ञान आधारित संस्थागत मंच है यह देश के सबसे बड़े ऋणदाता द्वारा भावी पीढ़ी के उद्योगों को पूँजी प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु एक रणनीतिक पहल है।
- **उद्देश्य:** यह पहल वर्ष 2030 तक भविष्य उन्मुख उद्योगों में 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक के पूँजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखती है तथा भारत की जलवायु वित्त व हरित परिवर्तन संरचना को मजबूती प्रदान करती है।

Daily Current Affairs

Date : 04 February, 2026



- **विज्ञान:** यह श्वेत पत्रों, परियोजना मूल्यांकन, रिपोर्ट, साझा मंच गोलमेज बैठकों के माध्यम से जानकारी प्रदान करेगी।

विशेषता:

- A. 8 उभरते (सनराइज़ सेक्टर्स) पर केन्द्रित: विकसित भारत विज्ञान @2047 के अनुरूप।

हरित ऊर्जा	नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन व अमोनिया और डी-कार्बोनाइज़ेशन
प्रौद्योगिकी एवं अवसंरचना	सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर अवसंरचना और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर
भविष्य की गतिशीलता	इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व उन्नत सेल रसायन (ACC)/बैटरी भंडारण

- B. **जोखिम प्रबंधन:** पारंपरिक थिंक-टैंक के विपरित चक्र को एक 'व्यावहारिक कार्यान्वय केंद्र' के रूप में तैयार किया गया जो जोखिम मॉडलों को विकसित करेगा।
- C. **वैश्विक साझेदारियाँ:** SBI ने संयुक्त परियोजना मूल्यांकन और सह वित्तपोषण हेतु जापान के MUFG और SMBC सहित 21 घरेलू व वैश्विक वित्तीय संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- D. **MSMEs:** उत्कृष्टता केंद्र चक्र का MSMEs तक विस्तार व सहयोग किया गया।

--:20:--

लोक प्रशासन

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

चर्चा में क्यों?

- उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 की धारा 17A की संवैधानिक वैधता पर विभाजित फैसला सुनाया।



मुख्य बिन्दु:

विभाजित फैसला:

- न्यायमूर्ति K. V. विश्वनाथन (शर्तों के साथ निर्णय बरकरार रखा): ईमानदार अधिकारियों को परेशान करने वाली तुच्छ शिकायतों से बचाने के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, इसकी वैधता सशर्त है - स्वीकृति किसी स्वतंत्र प्राधिकरण (केन्द्र; लोकपाल व राज्य; लोकायुक्त) की बाध्यकारी राय पर आधारित होनी चाहिए, न की स्वयं सरकार की।
- न्यायमूर्ति B. V. नागरत्ना (असंवैधानिक घोषित किया): इन्होंने धारा 17A को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे "पुरानी शराब को नए रूप में" बताया। इनके अनुसार यह अनुच्छेद-14 (कानून के समक्ष समानता) का उल्लंघन है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 :

परिचय व अधिनियमित :

- यह संथानम समिति (वर्ष 1962-64) की सिफारिशों के आधार पर अधिनियमित भारत का प्रमुख भ्रष्टाचार विरोधी कानून है।
- **लागू:** 9 सितंबर, 1988
- यह लोकसेवक की व्यापक परिभाषा में सरकारी कर्मचारियों, न्यायाधीशों और सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले किसी व्यक्ति को शामिल करता है तथा रिश्वतखोरी, अनुचित लाभ और आपराधिक दुराचार जैसे अपराधों को अपराध घोषित करता है।

धारा-17 A

- **उत्पत्ति :** भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में वर्ष 2018 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई।
- **उद्देश्य :** इस धारा को सद्भावना से लिए गए निर्णयों के लिए अधिकारियों को जाँच से बचाकर निर्णय लेने के लिए एक 'सुरक्षित क्षेत्र' बनाने के लिए अधिनियमित किया गया ताकि नौकरशाही में 'सुरक्षित रहने की प्रवृत्ति' को रोका जा सके।
- **प्रावधान:** धारा 17A के तहत जाँच एजेंसियों (CBI) को किसी लोक सेवक के आधिकारिक कृत्यों की जाँच शुरू करने से पूर्व संबंधित सरकारी प्राधिकरण से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु:

अन्य कानूनी मामले:

1. **विनीत नारायण बनाम भारत संघ (वर्ष 1998):**
 - सुप्रीम कोर्ट ने "सिंगल डायरेक्टिव" (कार्यकारी आदेश) को रद्द कर दिया।
 - अनुच्छेद-14 का उल्लंघन माना (निष्पक्ष जाँच में बाधा)।
2. **डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम CBI निदेशक (वर्ष 2014) :**
 - सर्वोच्च न्यायालय ने DSPE अधिनियम, 1946 की धारा 6A को निरस्त कर दिया। जिसमें संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों की जाँच के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य थी।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता, 2026

चर्चा में क्यों?

- 2 फरवरी, 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य भारत-अमेरिका व्यापार समझौता, 2026 पर सहमति बनी है, अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर प्रभावी शुल्क घटाकर 18% कर दिया है।



मुख्य बिन्दु:

- महत्त्व :** यह समझौता व्यापार तनाव को कम करने की दिशा में रणनीतिक कदम है और भारत को अमेरिका के प्रमुख सहयोगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को प्रतिसंतुलन के रूप में स्थापित करता है।

समझौते की मुख्य विशेषताएं:

- शुल्क में कमी :** अमेरिका ने भारतीय आयात पर पारस्परिक शुल्क 25% से घटाकर 18% कर दिया है।
- NOTE:** अतिरिक्त 25% दंडात्मक टैरिफ (आरोपित: अगस्त, 2025 तथा कारण : रूसी तेल खरीद) को प्रभावी रूप से हटाया गया जिससे कुल प्रभावी टैरिफ 50% से घटकर 18% हो गया है।

2. भारत की प्रतिबद्धताएँ :

- **बाजार शुल्क:** भारत द्वारा अमेरिका पर लगाए गए शुल्क व गैर-शुल्क बाधाओं को घटाकर शून्य करने की संभावना है।
- **ऊर्जा/ईंधन खरीद :** समझौते के तहत भारत ने रूसी तेल की खरीद को काफी कम करने पर सहमति व्यक्त की है।
- **'बाय अमेरिकन' नीति:** भारत ने सरकारी व औद्योगिक खरीद के लिए 'बाय अमेरिकन' के प्रति प्रतिबद्धता जताई है।

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार संबंध:

- **कुल द्विपक्षीय व्यापार :** वर्ष 2025 में 132 अरब डॉलर।
- **कुल अधिशेष:** वर्ष 2025 में भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष 40.82 अरब डॉलर रहा।
- **आयात-निर्यात :**

वित्त वर्ष 2025

अमेरिका से आयात	अमेरिका को निर्यात
<ul style="list-style-type: none">■ खनिज ईंधन व तेल■ कीमती व अर्द्ध कीमती पत्थर व धातु■ परमाणु रिएक्टर व मशीनरी■ विद्युत उपकरण	<ul style="list-style-type: none">■ विद्युत मशीनरी■ बहुमूल्य व अर्द्ध बहुमूल्य पत्थर व धातुएँ■ औषधीय उत्पाद■ मशीनरी व यांत्रिक उपकरण■ खनिज ईंधन■ लौह व इस्पात वस्तुएँ

- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) :** भारत में अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है जिसने वर्ष 2000 से 2025 तक कुल 70.65 बिलियन डॉलर का FDI किया है।

रणनीतिक लक्ष्य:

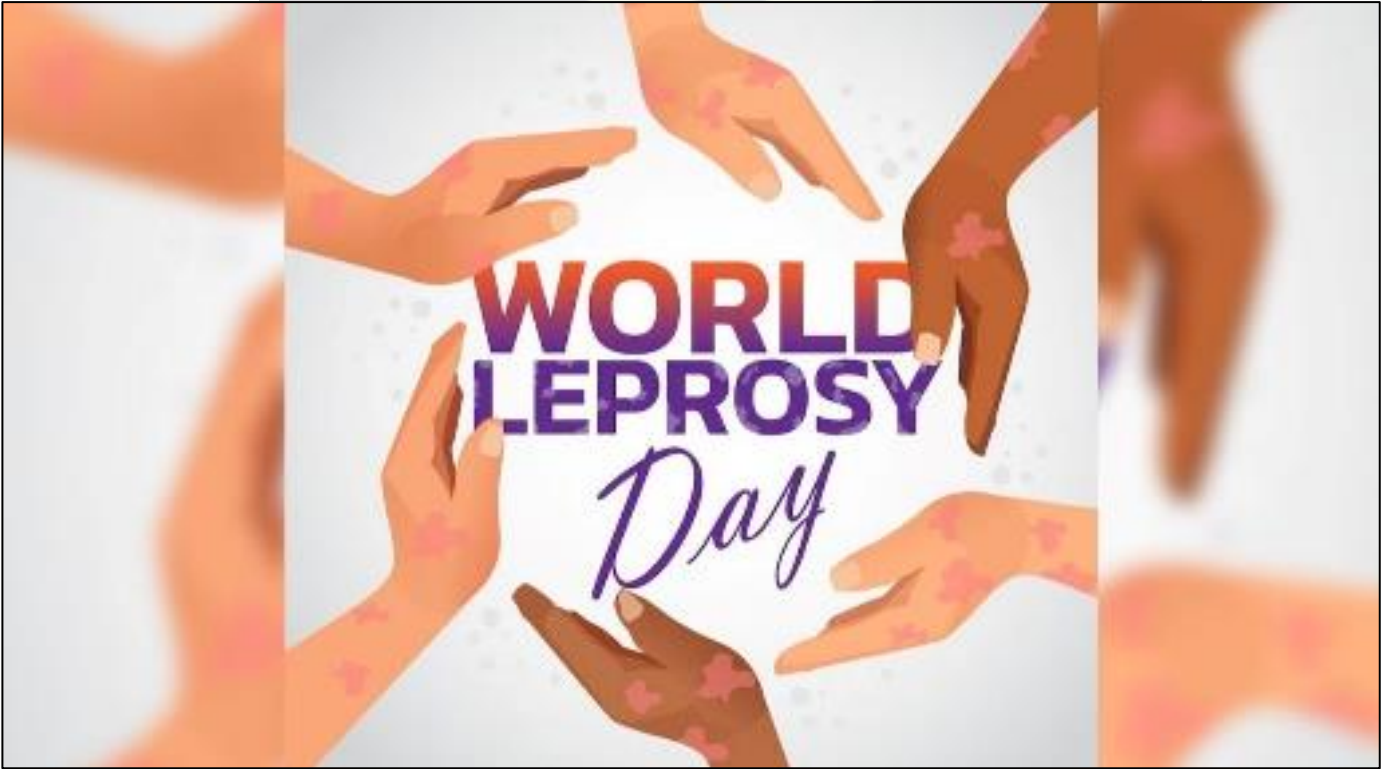
- **'मिशन 500' :** द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक 500 अरब डॉलर तक बढ़ाना।
- अमेरिका-भारत कॉम्पैक्ट (सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के अवसरों को उत्प्रेरित करना) वर्ष 2025 में शुरू किया गया।

⌚ विज्ञान प्रौद्योगिकी 🌡️

कुष्ठ रोग

📢 चर्चा में क्यों?

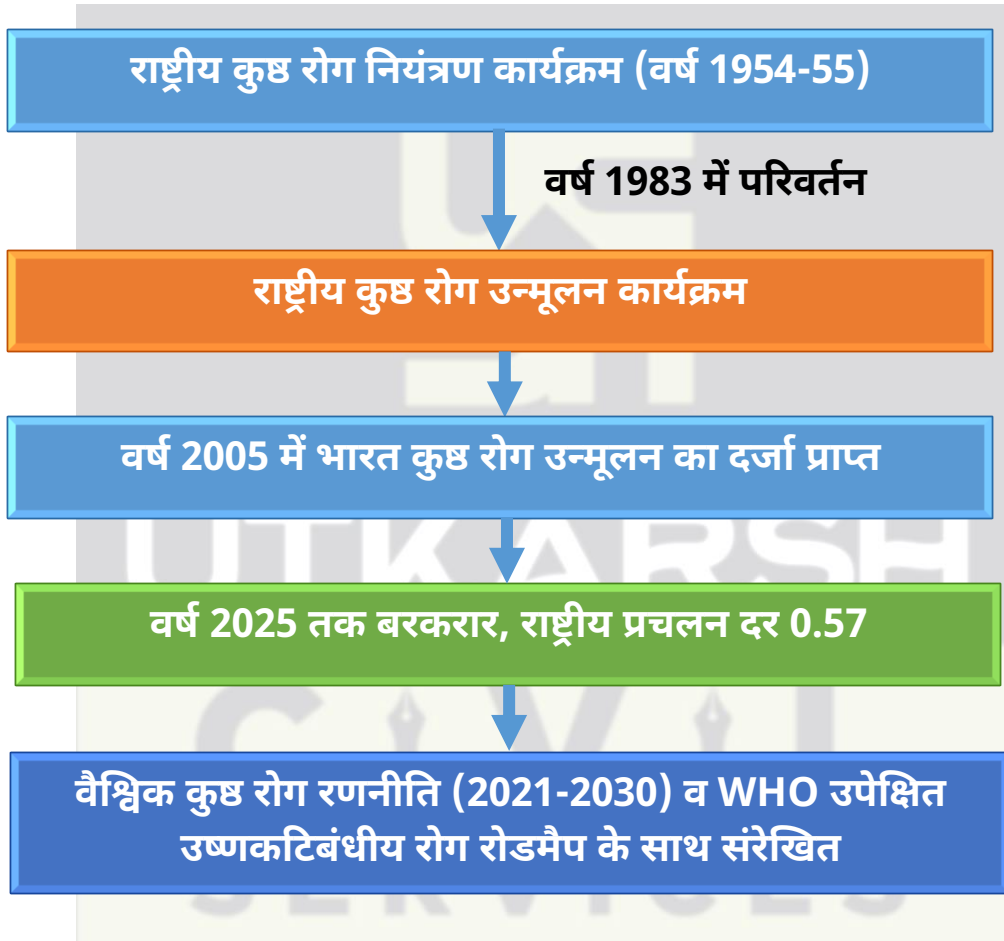
- राष्ट्रीय कुष्ठ रोग दिवस (जनवरी के अंतिम रविवार) पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुष्ठ रोग से संबंधित जागरूकता, शीघ्र निदान हेतु एक सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) कार्यक्रम आयोजित किया।



📌 मुख्य बिन्दु:

- कुष्ठ रोग : दीर्घकालिक संक्रमण रोग।
- रोगकारक : माइकोबैक्टीरियम लेप्री (बैक्टीरिया)
- प्रभावित अंग: त्वचा व परिधीय तंत्रिका तंत्र ।
- संचारण : अनुपचारित मामलों से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैलता है।

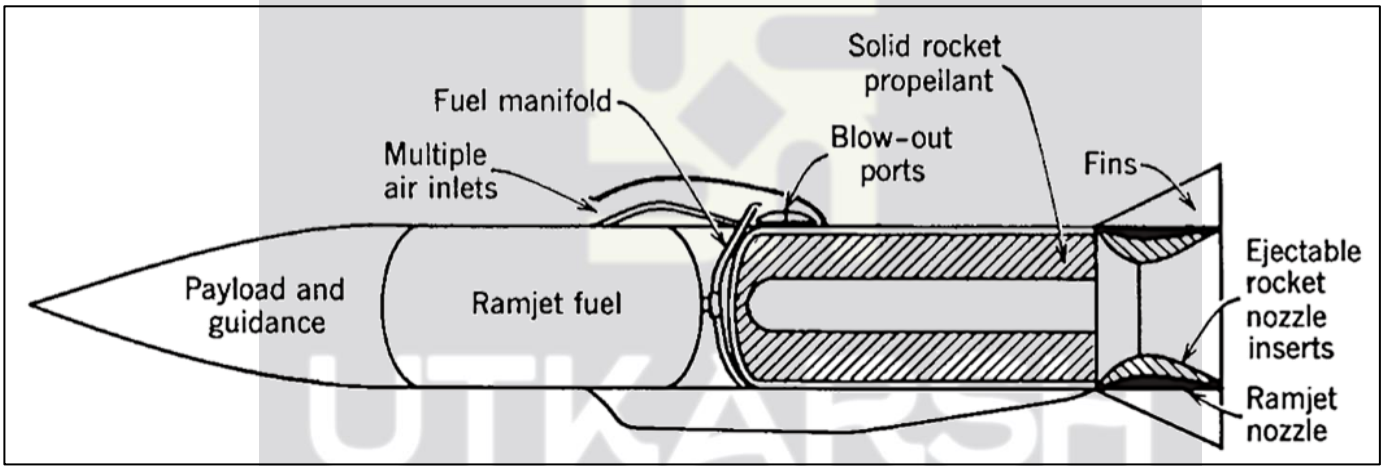
- **उपचार:** मल्टीड्रग थेरेपी (MDT)।
- **लक्षण:** संवेदी क्षमता में कमी, त्वचा पर लाल धब्बे, मांसपेशियों की कमजोरी और पक्षाघात।
- **भारत के प्रयास:** राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम:



ठोस ईंधन डक्टेड रैमजेट तकनीक

चर्चा में क्यों?

- 3 फरवरी, 2026 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने ओडिशा तट पर स्थित चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) से ठोस ईंधन डक्टेड रैमजेट (SFDR) तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया।



मुख्य बिन्दु:

- प्रक्षेपण की निगरानी :** डिफेंस रिसर्च एंड डवलपमेंट लेबोरेट्री, हाई एनर्जी मटीरियल्स रिसर्च लेबोरेट्री, रिसर्च सेंटर बिल्डिंग और ITR (DRDO प्रयोगशालाएँ)।
- उप प्रणालियों का प्रदर्शन :** नोजल-लेस बूस्टर, ठोस ईंधन डक्टेड रैमजेट मोटर और फ्यूल कंट्रोलर।

सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (SFDR) तकनीक:

- परिचय:** SFDR तकनीक रैमजेट इंजन सिद्धांत पर आधारित एक मिसाइल प्रणोदन प्रणाली है।
- प्रणाली:** यह प्रणाली ठोस ईंधन से चलने वाली वायु श्वास रैमजेट इंजन का उपयोग करती है।

Daily Current Affairs

Date : 04 February, 2026



- ठोस प्रणोदक रॉकेटों के विपरित, रैमजेट उड़ान के दौरान वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, इस प्रकार यह हल्का होता है और अधिक ईंधन के साथ ले जा सकता है।
- **इतिहास :** सर्वप्रथम वर्ष 2017 में DRDO ने SFDR का विकास किया तथा वर्ष 2018 व 2019 में सफल परीक्षण किए।

महत्त्व:

1. इस तकनीक के सफल प्रदर्शन से DRDO को स्वदेशी लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को विकसित करने में मदद मिलेगी।
2. इस उपलब्धि के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जिनके पास यह अत्याधुनिक तकनीक है।
3. SFDR तकनीक पर आधारित मिसाइल सुपरसोनिक गति से लक्ष्य तक पहुँचती है।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--:28:--